तालबिान पर भारत की अवस्थति (The shift in India position on Taliban)

संदर्भ

हाल ही में भारत ने 'मॉस्को फॉर्मेट' की बहुपक्षीय बैठक में 'गैर-आधकिारकि' प्रतभिागियों के रूप में दो पूर्व राजनयकिों को भेजा था। गौरतलब है कि इस बैठक में तालबिानी प्रतनिधियिों को भी शामलि कयिा गया था। भारतीय राजनयकिों में अफगानस्तिान के पूर्व राजदूत अमर सनि्हा और पाकस्तिान के पूर्व उच्चायुक्त टी. सी. ए. राघवन शामलि थे। वर्तमान में सनि्हा और राघवन वदिश मंत्रालय द्वारा वत्तिपोषति अलग-अलग थकि टैंक से संबद्ध हैं।

नए संबंध

- 1999 में IC-814 के अपहरण के बाद यह पहला मौका था जब भारत सरकार के प्रतनिधि सार्वजनकि रूप से तालबिान से जुड़े मामलों में शामलि हुए हैं।
- गौरतलब है कि इससे पहले आईबी के अजीत डोभाल, रॉ (RAW) के सी. डी. सहाय और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ए. आर. घनश्याम जैसे भारतीय अधकिारयिों ने मुतवक्कलि की अध्यक्षता में तालबिान शासन के संवाददाताओं से बात की थी।
- उक्त बहुपक्षीय बैठक में अफगानस्तिान ने वदिश मंत्रालय की बजाय अफगान हाई पीस कौंसलि से दो प्रतनिधि भेजे जनिके साथ रूस के राजदूत भी शामलि थे।
- अफगान हाई पीस कौंसलि (HPC) अफगानस्तिान सरकार द्वारा स्थापति कयिा गया एक ऐसा मंच है जो शांति तथा सुलह सुनशि्चति कराता है।
- भागीदारी का स्तर तय करने हेतु भारत तथा अफगानस्तिान के मध्य परामर्श पहले ही हो चुका था।
- भारतीय प्रतनिधियिों ने बैठक के दौरान कोई वक्तव्य नहीं दयिा।
- यह पहली बार था जब भारत सरकार द्वारा नामति प्रतनिधि तालबिान प्रतनिधिमिंडल के साथ बैठक में शामलि हुए। इसे तालबिान के संदर्भ में भारत की अवस्थति में बदलाव के रूप में माना जा सकता है।
- भारत द्वारा कयिा गया अपने प्रतनिधियिों का चुनाव भारत की गंभीरता को स्पष्ट कर देता है। प्रतनिधिमिंडल में शामलि सनि्हा काबुल की परस्थितियिों से सुपरचिति हैं, जबकि राघवन, जसवंत सहि के सहायक तथा 2003 से 2007 तक पाकस्तिान के भारतीय उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही राघवन पाकस्तिान, ईरान और अफगानस्तिान के संयुक्त सचवि के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

पुराने संबंध

- भारत उन देशों में से एक है जन्होंने 1996-2001 के तालबिानी शासन को मान्यता देने से इनकार कर दयिा था।
- 1999 में IC-814 के अपहरण के दौरान भारत को समझौते के लयि मजबूर कयिा गया था, जबकि कई अन्य मामलों में भारत ने तालबिान-वरिोधी ताकतों को सहायता भी प्रदान की थी।
- 1990 के दशक के दौरान भारत ने अफगानस्तिान में पाकस्तिान प्रायोजति तालबिान शासन से लड़ने वाले उत्तरी गठबंधन को सैन्य और वत्तिीय सहायता भी प्रदान की थी।
- तालबिान-वरिोधी उत्तरी गठबंधन ताकतों का नेतृत्व कर रहे अहमद शाह मसूद ने 2001 में भारत का भ्रमण भी कयिा था जसिके कुछ महीनों बाद उनकी हत्या कर दी गई थी।
- अहमद मसूद ने तत्कालीन भारतीय वदिश मंत्री से भी मुलाकात की थी। मसूद ने उस समय बताया था कि IC-814 के अपहरणकर्त्ता पाकस्तिान से थे तथा इस अपहरण के लयि तालबिान ने सहायता प्रदान की थी।
- 9/11 का हमला तथा अमेरकिी कार्रवाई के बाद तालबिानी शासन के अंत के उपरांत 2001 में हामदि करजई के शासन की शुरुआत के शुभअवसर पर तत्कालीन भारतीय वदिश मंत्री जसवंत सहि काबुल गए थे। तत्पश्चात् भारत ने अफगानस्तिान में पुनः अपना राजदूत भेजना शुरू कर दयिा था।
- तालबिान 2006-07 के दौरान एक बार फरि उठ खड़ा हुआ और अमेरकिी सेना के लयि चुनौती बन गया। भारत ने तालबिान से दूरी बनाए रखी।
- समय के साथ तालबिान की ताकत बढ़ती गई और अंत में अमेरकिा ने 2009 में अपनी सेना वापस बुला ली तथा करजई सरकार शांति एवं सुलह हेतु तालबिान के समक्ष पहुँच गई।

हालयिा बदलाव

- 2010 में, लंदन में अफगानस्तिान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत ने एक बदली हुई अवस्थति को अपनाया।
- भारत ने कहा था कि यह अफगानस्तिान की चुनी हुई सरकार की ज़म्मिेदारी है कि वह तालबिान के साथ वार्ता हेतु नयिम और शर्तें तथा मानदंड तय करे।
- अफगान सरकार ने कहा था कि 'तालबिान को अफगान संवधािन स्वीकार करना होगा, हसिा छोड़नी होगी और अल-कायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ सभी प्रकार के संबंध तोड़ने होंगे।' सम्मेलन में इस बात का समर्थन कयिा गया।

- हालाँकि 'मॉस्को फॉर्मेट' की बहुपक्षीय बैठक में भारत ने तालिबान से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता नहीं की लेकिन फिर भी इसने तालिबान द्वारा उक्त शर्तों को अपनाए जाने का अनुमोदन किया।
- अशरफ घानी की सरकार के सत्ता में आने के बाद, अफगानिस्तान ने तालिबान के साथ सुलह के मकसद से पाकिस्तान से सहायता की उम्मीद की थी। किंतु तालिबान की आतंकी घटनाओं ने इन कोशिशों को असफल कर दिया।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका, चीन और रूस ने अफगान सरकार तथा तालिबान के बीच सुलह एवं शांति वार्ता की शुरुआत की, इसके साथ ही भारत ने अपनी अवस्थिति में भी बदलाव किया है।
- भारत ने ऐसे मानदंडों को अपनाने पर ज़ोर दिया जिसमें शांति प्रक्रिया केवल 'अफगानिस्तान के नेतृत्व वाली' तथा 'अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली' होगी।
- हालाँकि मौजूदा बहुपक्षीय प्रयास को कई लोग अफगानिस्तान के नेतृत्व के तहत नहीं मान रहे हैं क्योंकि इस बैठक का नेतृत्व रुस और अमेरिका कर रहे हैं।
- गैर-आधिकारिक स्तर पर होने के बावजूद भी इस बैठक में भारत की भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण है, भले ही शुरुआत में पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में रुचि ले रहा है।

निष्कर्ष

युद्ध के मैदान में कट्टरपंथी विचारधाराओं तथा धर्म से संचालित होने वाले लोगों को पराजित कर पाना मुश्किल है, खासकर तब, जब उनकी सैन्य ताकत को राज्य का समर्थन प्राप्त हो और जैसा कि तालिबान के मामले में है। तेज़ी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौर में भारत के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया जाए। अगर यह बहुपक्षीय बैठक सफल हो जाती है तो दक्षिणी एशिया में भारत मज़बूत बनकर उभरेगा। हालाँकि भारत इस वार्ता में विश्वास के साथ शामिल हो रहा है, लेकिन इसके नियम और शर्तें क्या हैं यह एक बड़ा सवाल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/The-shift-in-India-position-on-Taliban